भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 834
दिनांक 04.12.2025 को उत्तर के लिए नियत

"लघु उद्यमों का प्रौद्योगिकी उन्नयन और डिजिटलीकरण"

834. श्रीमती मालविका देवी:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा देश भर में लघु उद्यमों का प्रौद्योगिकी उन्नयन और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या इससे जुड़ी कोई योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आकांक्षी जिलों या पिछड़े इलाकों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) प्रौद्योगिकी सेंटर बनाने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं, यदि हाँ, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने के लिए कोई कदम उठा रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) एवं (ख): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय देश भर में लघु उद्यमों के प्रौद्योगिकी उन्नयन और डिजिटीकरण के संवर्धन हेतु विभिन्न स्कीम और पहलों का कार्यान्वयन कर रहा है जिनमें अन्य के साथ-साथ एमएसई-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सामान्य सुविधा केंद्र), टूल रूम / प्रौद्योगिकी केंद्र, सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) - परिवर्तन के लिए हरित निवेश वित्तपोषण (गिफ्ट) स्कीम और एमएसएमई चैंपियंस स्कीम शामिल हैं। ये पहलें आधुनिकीकरण, कौशल और गुणवत्ता वृद्धि, उन्नत प्रौद्योगिकी पहुंच, हरित प्रौद्योगिकी अंगीकरण और एमएसएमई की बेहतर प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए सहायता प्रदान करती हैं। सरकार उद्यम पोर्टल, एमएसएमई चैंपियंस पोर्टल, सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम), व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (ट्रेड्स), एमएसएमई मार्ट, एमएसएमई संबंध और ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) पोर्टल जैसी पहलों के माध्यम से डिजिटीकरण को बढ़ावा दे रही है, जिनसे डिजिटल पंजीकरण, ऑनलाइन खरीद, ई-मार्केट पहुंच, प्राप्य वित्तपोषण और शिकायत निवारण सुविधाजनक हुआ है और देश भर में एमएसएमई को सहायता प्राप्त हो रही है।

(ग): सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय प्रौद्योगिकी, कुशल मानव संसाधनों और परामर्शदात्री सेवाओं के लिए एमएसएमई की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार समाधान प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी केंद्रों के नेटवर्क की भौगोलिक पहुंच को बढ़ाने हेतु देश भर में 20 नए प्रौद्योगिकी केंद्र (टीसी) और 100 विस्तार केंद्र (ईसी) स्थापित करने के लिए 'नए प्रौद्योगिकी केंद्रों/विस्तार केंद्रों की स्थापना' नामक स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। इससे तृणमूल स्तर पर एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता और लाभप्रदता में बढ़ोतरी होगी। स्कीम के अंतर्गत, नए प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना के लिए 20 स्थानों को मंजूरी दी गई है, जिनमें आकांक्षी जिलों- गया (बिहार) और बोकारो (झारखंड) में दो स्थान शामिल हैं।

(घ): एमएसएमई मंत्रालय ने अपने फील्ड संगठनों अर्थात् एमएसएमई-विकास कार्यालयों, एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्रों और एमएसएमई परीक्षण केंद्रों में 65 निर्यात सुविधा केंद्र (ईएफसी) की स्थापना की है जिसका उद्देश्य एमएसएमई को उनकी निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए अपेक्षित परामर्श और सहायता प्रदान करना है।

****